IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन (CCE) की प्रभावशीलता का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"

Prof. Indu Sharma1, Dr. Rajesh Dhaka2

1Dean & HOD, 2Assistant Professor

Department of Education, Jagannath University, Bahadurgarh

सारांश :

सतत एवं समग्र मूल्यांकन (CCE) एक ऐसी विद्यालय-आधारित मूल्यांकन प्रणाली है, जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उनके शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक दोनों पहलुओं का समग्र आकलन करती है। यह एक विकासात्मक एवं छात्र-केंद्रित मूल्यांकन प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य केवल ज्ञान का मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं व्यवहारिक विकास को सुनिश्चित करना भी है। इस प्रणाली के दो प्रमुख आयाम हैं—सततता, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, तथा समग्रता, जिसके अंतर्गत अधिगम के विविध आयामों का व्यापक आकलन किया जाता है। प्रस्तुत शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों—प्रारंभिक, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक—पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना है। साथ ही, यह अध्ययन वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की उपयोगिता, उसके क्रियान्वयन तथा विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों पर उसके प्रभाव का परीक्षण करता है। यह अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है, जिसमें द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली विद्यार्थियों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करती है, अधिगम में निरंतरता बनाए रखती है तथा परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करने में सहायक होती है। तथापि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षकों के अपर्याप्त प्रशिक्षण, संसाधनों की कमी एवं समय के अभाव जैसी चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। अतः सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता एवं योजनाबद्ध क्रियान्वयन आवश्यक है।

मुख्य शब्द :सतत एवं समग्र मूल्यांकन (CCE), प्रभावशीलता, विद्यालयी शिक्षा, अधिगम परिणाम, समग्र विकास, मूल्यांकन प्रक्रिया, शैक्षिक सुधार

परिचय

शिक्षा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि निर्धारित अधिगम उद्देश्यो की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अतः इसके मूल्यांकन की प्रक्रिया भी निरंतर और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। यदि अधिगम की प्रगति का समय-समय पर आकलन नहीं किया जाए, तो यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं। विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य केवल विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण करना नहीं है, बल्कि उन्हें उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना भी है। इसके साथ ही, मूल्यांकन विद्यार्थियों के जीवन कौशल जैसे—समस्या समाधान क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, संप्रेषण कौशल तथा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, मूल्यांकन शिक्षा को अधिक सार्थक, उपयोगी एवं जीवनोपयोगी बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE, 1986) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन की प्रकृति रचनात्मक एवं विकासात्मक होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यालय स्तर पर बालक अधिगम के निर्माणात्मक चरण में होता है, जहाँ उसका बौद्धिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास तीव्र गति से हो रहा होता है। इसलिए इस स्तर पर मूल्यांकन का उद्देश्य त्रुटियों को उजागर करना नहीं, बल्कि अधिगम को सुदृढ़ बनाना और विद्यार्थियों को निरंतर प्रगति के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की अवधारणा विकसित की गई, जो पारंपरिक परीक्षा प्रणाली की सीमाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास पर बल देती है। यह प्रणाली केवल वर्षांत परीक्षा तक सीमित न रहकर पूरे शैक्षणिक सत्र में निरंतर मूल्यांकन पर आधारित होती है, जिससे विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार के लिए समय पर हस्तक्षेप संभव हो पाता है।

प्रस्तुत शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की अवधारणा का विस्तृत अध्ययन करना।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन के स्वरूप एवं उपयोगिता का विश्लेषण करना।
- सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों एवं बाधाओं की पहचान करना।
- विद्यालयी शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु व्यवहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

यह अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है, जिसमें द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस शोध में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली के समक्ष उपस्थित चुनौतियों एवं बाधाओं की पहचान की गई है...

परिभाषा एवं अवधारणा

सतत मूल्यांकन का आशय मूल्यांकन की उस प्रक्रिया से है, जो निरंतर एवं नियमित रूप से संचालित होती है। इसमें अधिगम के प्रत्येक चरण पर विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन किया जाता है। यह केवल वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दैनिक कक्षा गतिविधियों, मौखिक परीक्षणों, लिखित कार्यों, परियोजनाओं (Projects), असाइनमेंट्स एवं कक्षा सहभागिता के माध्यम से भी किया जाता है।

सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख तत्व सम्मिलित होते हैं—

- नियमित मूल्यांकन : विद्यार्थियों की प्रगति का समय-समय पर आकलन।
- इकाई परीक्षण : प्रत्येक अध्याय या इकाई के पश्चात् लघु परीक्षण।
- अधिगम अंतराल की पहचान : विद्यार्थियों की कमजोरियों का पता लगाना।
- सुधारात्मक शिक्षण : कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष सहायता प्रदान करना।
- पुनः परीक्षण : सुधार के बाद पुनः मूल्यांकन करना।
- प्रतिपुष्टि : विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सुधार हेतु आवश्यक सुझाव देना।

इस प्रकार, सतत मूल्यांकन विद्यार्थियों को निरंतर सुधार का अवसर प्रदान करता है और उन्हें अपने अधिगम के प्रति अधिक जागरूक बनाता है।

समग्र मूल्यांकन

समग्र मूल्यांकन का अर्थ विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं का आकलन करना है। यह केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सह-शैक्षणिक क्षेत्रों, जैसे—व्यक्तित्व विकास, रचनात्मकता, खेल-कूद, कला, नैतिक मूल्य एवं सामाजिक व्यवहार को भी समाहित करता है।

समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत विभिन्न उपकरणों एवं तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे—

- लिखित परीक्षा
- मौखिक परीक्षा
- प्रोजेक्ट कार्य
- अवलोकन
- चेकलिस्ट एवं रेटिंग स्केल

- सहपाठी एवं आत्ममूल्यांकन

इस प्रकार, समग्र मूल्यांकन विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व के संतुलित विकास को सुनिश्चित करता है।

सतत एवं समग्र मूल्यांकन (CCE) की समग्र अवधारणा

सतत एवं समग्र मूल्यांकन एक ऐसी समेकित मूल्यांकन प्रणाली है, जो सततता एवं समग्रता दोनों को समाहित करती है। यह एक विद्यालय-आधारित एवं शिक्षक-निर्देशित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान, समझ, कौशल एवं व्यवहार का समग्र मूल्यांकन करना है।

सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन विधियों का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अवलोकन करते हैं। यह प्रक्रिया पूरे शैक्षणिक वर्ष में चलती रहती है और शिक्षक-विद्यार्थी के बीच नियमित अंतःक्रिया (Interaction) का हिस्सा होती है।

विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समय-समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी कमजोरियों को पहचानकर उनमें सुधार कर सकें। साथ ही, शिक्षक यह निर्धारित कर पाते हैं कि—

- किन विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है,
- किन्हें पुनरावृत्ति एवं सुधारात्मक शिक्षण की जरूरत है,
- और कौन से विद्यार्थी उच्च स्तर के अधिगम के लिए तैयार हैं।

इस प्रकार, सतत एवं समग्र मूल्यांकन न केवल अधिगम को अधिक प्रभावी बनाता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि सभी विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार निरंतर प्रगति करें। इससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि होती है और उनका समग्र विकास संभव हो पाता है।

सतत एवं समग्र मूल्यांकन की विशेषताएँ

सतत एवं समग्र मूल्यांकन एक ऐसी समेकित मूल्यांकन प्रणाली है, जो विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आयामों में उनके अधिगम का आकलन करती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

सतत : सतत एवं समग्र मूल्यांकन में मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है।

अनौपचारिक : यह केवल औपचारिक परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कक्षा की दैनिक गतिविधियों, संवाद, सहभागिता एवं व्यवहार के माध्यम से भी किया जाता है।

आवधिक :नियत अंतराल पर परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की प्रगति का नियमित आकलन संभव हो सके।

शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक : यह विद्यार्थियों के शैक्षणिक (पाठ्य विषय) तथा सह-शैक्षणिक (जैसे—खेल, कला, नैतिकता, व्यवहार) दोनों पक्षों का मूल्यांकन करता है।

रचनात्मक एवं समापनात्मक :सतत एवं समग्र मूल्यांकन में रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से निरंतर सुधार पर बल दिया जाता है, जबकि समापनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से अंतिम उपलब्धि का आकलन किया जाता है।

निदानात्मक :यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं अधिगम अंतराल की पहचान करता है, ताकि उचित सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

प्रभावी प्रतिपुष्टि :विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समय-समय पर उपयोगी एवं रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है।

प्रेरणा एवं आत्म-सम्मान :सतत एवं समग्र मूल्यांकन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, प्रेरणा एवं सकारात्मक आत्म-सम्मान का विकास करता है।

सुधार का अवसर :विद्यार्थियों को अपनी गलतियों से सीखने एवं सुधार करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं।: सामाजिक संबंधों का विकास :यह विद्यार्थियों में सहयोग, सहभागिता एवं सामाजिक संबंधों के विकास को बढ़ावा देता है।

तनाव में कमी :निरंतर एवं बहुआयामी मूल्यांकन के कारण परीक्षा का दबाव कम होता है, जिससे विद्यार्थियों का तनाव घटता है।

बहुआयामी अनुभव

सतत एवं समग्र मूल्यांकन विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करता है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास संभव होता है।

सतत एवं समग्र मूल्यांकन का व्यापक दृष्टिकोण

शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक सभी पहलू सम्मिलित होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मूल्यांकन प्रक्रिया भी इन सभी आयामों को ध्यान में रखकर की जाए।

वर्तमान समय में प्रायः यह देखा जाता है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन केवल उनके शैक्षणिक परिणामों के आधार पर किया जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि विद्यार्थियों के प्रयास , प्रदर्शन अधिगम के प्रति दृष्टिकोण , व्यवहारिक जीवन में ज्ञान के अनुप्रयोग तथा रचनात्मकता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का समुचित आकलन नहीं किया जाता।

इस स्थिति को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक समग्र बनाया जाए। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन कक्षा के भीतर और बाहर, विभिन्न परिस्थितियों एवं वातावरणों में किया जाना चाहिए।

साथ ही, मूल्यांकन केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि विद्यालय एवं शिक्षकों के लिए भी एक प्रतिपुष्टि तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसके माध्यम से यह पता चलता है कि विद्यालय एवं शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में कितने सफल रहे हैं।

सतत एवं समग्र मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों को—

- विभिन्न विषयों में आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने का अवसर मिलता है,
- विभिन्न विषय क्षेत्रों में अपेक्षित स्तर की उपलब्धि प्राप्त करने में सहायता मिलती है,
- उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं, रुचियों, दृष्टिकोण एवं प्रेरणा का विकास होता है,
- तथा वे एक स्वस्थ, संतुलित एवं उत्पादक जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं।

सहकारी उपक्रम

- सतत एवं समग्र मूल्यांकन एक सहकारी उपक्रम है, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाचार्य, अभिभावक एवं समुदाय सभी की सक्रिय सहभागिता आवश्यक होती है। यह एक ऐसी समेकित मूल्यांकन प्रक्रिया है, जिसमें सभी हितधारकों के सहयोग से ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रणाली में विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया में उसकी सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम शैली भिन्न होती है और वह केवल कक्षा में ही नहीं, बल्कि विभिन्न अनुभवों एवं गतिविधियों के माध्यम से भी ज्ञान अर्जित करता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों को बहुआयामी कौशल विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे वे आत्ममूल्यांकन करने में सक्षम बनते हैं और अपने अधिगम के प्रति अधिक जिम्मेदार बनते हैं।
- शिक्षक एवं प्रधानाचार्य इस प्रक्रिया के प्रमुख प्रेरक होते हैं, जो विद्यार्थियों को आवश्यक अवसर एवं संसाधन उपलब्ध कराते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अवलोकन करते हैं तथा उनके व्यवहार एवं अधिगम से संबंधित दैनिक अभिलेख तैयार करते हैं, जिससे वे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझकर उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। प्रधानाचार्य इस पूरी प्रक्रिया के प्रभावी संचालन के लिए प्रशासनिक सहयोग, समन्वय एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं।
- अभिभावक भी सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली के महत्वपूर्ण भागीदार होते हैं, जो अपने बच्चों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विद्यालय द्वारा आयोजित अभिभावक-शिक्षक बैठकों के माध्यम से उनके साथ नियमित संवाद स्थापित किया जाता है, जिससे वे अपने बच्चों की प्रगति से अवगत हो सकें और शिक्षकों के साथ मिलकर उनके समग्र विकास में सहयोग कर सकें। वे अपने बच्चों को विभिन्न शैक्षणिक एवं सह-

शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनके संतुलित व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाता है।

- समुदाय भी सतत एवं समग्र मूल्यांकन के उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ने का कार्य करता है। समुदाय के माध्यम से विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों, परियोजनाओं एवं व्यावहारिक अनुभवों में भाग लेने का अवसर मिलता है, जिससे उनका सामाजिक एवं नैतिक विकास होता है। इस प्रकार, सतत एवं समग्र मूल्यांकन एक सहयोगात्मक एवं समन्वित प्रक्रिया है, जिसमें सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास से ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।

कुछ अनुभवजन्य अध्ययन

सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संदर्भ में विभिन्न शोधों एवं अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रणाली शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किन्तु इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, USAID/Malawi तथा Malawi Ministry of Education, Science and Technology (MOEST) ने मिलकर कक्षा 3 में शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु सतत मूल्यांकन मॉडल को लागू करने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत USAID द्वारा वित्तपोषित Improving Educational Quality (IEQ) II टीम को 21 प्राथमिक विद्यालयों में इस मॉडल के विकास एवं व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य सौंपा गया। Malawi Institute of Education की टीम का उद्देश्य शिक्षकों को पारंपरिक निरंतर परीक्षण पद्धति से हटाकर ऐसी शिक्षण विधियों की ओर ले जाना था, जो उच्च स्तरीय चिंतन को विकसित करें।

इस अध्ययन में Ntcheu जिले के 122 विद्यार्थियों (जहाँ CCE लागू किया गया) तथा Mangochi और Balaka जिलों के 603 विद्यार्थियों (जहाँ यह लागू नहीं था) का मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ (मार्च 2002) और अंत (अक्टूबर 2002) में किया गया। परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि Ntcheu जिले के विद्यार्थियों ने अन्य जिलों की तुलना में अधिक प्रगति की। उदाहरणस्वरूप, Ntcheu के विद्यार्थी मार्च में औसतन 14 सामान्य अंग्रेजी शब्द पहचान पाते थे, जो अक्टूबर तक बढ़कर 41 हो गए, जबकि अन्य जिलों के विद्यार्थियों की संख्या केवल 9 से बढ़कर 22 तक पहुँची। इसी प्रकार गणित में Ntcheu के विद्यार्थियों की सही उत्तर देने की क्षमता 43% से बढ़कर 63% हो गई, जबकि अन्य जिलों में यह वृद्धि केवल 6% रही।

इसके अतिरिक्त, Ntcheu जिले के विद्यालयों में शिक्षकों ने अपनी कक्षाओं को अधिक आकर्षक एवं अधिगम-उन्मुख वातावरण में परिवर्तित किया, जहाँ विभिन्न शिक्षण सामग्री जैसे—गणितीय उपकरण, चार्ट एवं अन्य संसाधनों का उपयोग किया गया। अभिभावकों एवं समुदाय की सहभागिता भी इन विद्यालयों में बढ़ी। इस मॉडल की सफलता को देखते हुए इसे पूरे देश में लागू करने की संभावना पर विचार किया गया।

भारतीय संदर्भ में, अर्चना भट्टाचार्य एवं निर्मला शर्मा ने असम के जोरहाट जिले के प्राथमिक विद्यालयों में सह-शैक्षणिक गतिविधियों की स्थिति का अध्ययन किया। इस अध्ययन में 50 विद्यालयों का चयन किया गया तथा डेटा

संग्रह के लिए साक्षात्कार, अवलोकन, समूह चर्चा एवं अभिलेखों का उपयोग किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि विद्यालयी कार्यक्रमों में सह-शैक्षणिक गतिविधियों को उचित स्थान नहीं मिला है। शिक्षकों को इन गतिविधियों के संचालन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया था तथा इनका नियमित मूल्यांकन भी नहीं किया जाता था। परिणामस्वरूप, पाठ्यक्रम का सह-शैक्षणिक भाग लगभग उपेक्षित ही रहा।

इसी प्रकार, मंजुला पी. राव एवं पुरुषोत्तम राव ने तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की मूल्यांकन पद्धतियों का अध्ययन किया। इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि सतत मूल्यांकन को व्यवस्थित रूप से लागू नहीं किया जा रहा था। मूल्यांकन के अभिलेखों के लिए कोई समान प्रारूप नहीं था और शिक्षक केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए विद्यार्थियों के सामने चिह्न (✓) लगाकर रिकॉर्ड तैयार कर रहे थे। अधिगम कठिनाइयों की पहचान नहीं की जाती थी और न ही सुधारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता था। प्रगति पत्रों में केवल त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम दर्शाए जाते थे, जबकि सतत मूल्यांकन एवं सह-शैक्षणिक पहलुओं को नजरअंदाज किया जाता था।

क्षेत्रीय स्तर पर किए गए अन्य अध्ययनों (मंजुला राव, 1998, 2001, 2002 आदि) से यह निष्कर्ष सामने आया कि विद्यालयों में मूल्यांकन की पद्धतियाँ अभी भी पारंपरिक हैं। सतत मूल्यांकन को व्यवस्थित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है, भले ही शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले चुके हों। विद्यार्थियों की क्षमताओं का आकलन योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया जाता और अक्सर केवल रटने पर आधारित प्रश्नों पर अधिक जोर दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की वास्तविक समझ एवं अनुप्रयोग क्षमता का सही आकलन नहीं हो पाता।

इसके अतिरिक्त, रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान नहीं की जाती, अधिगम कठिनाइयों की पहचान नहीं होती तथा सुधारात्मक शिक्षण का अभाव रहता है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का मूल्यांकन भी प्रायः नहीं किया जाता, क्योंकि शिक्षकों में इस संबंध में जागरूकता एवं प्रशिक्षण की कमी होती है

सतत एवं समग्र मूल्यांकन का राजनीतिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य

सतत एवं समग्र मूल्यांकन की अवधारणा भारत की शैक्षिक नीतियों एवं सुधारों का एक महत्वपूर्ण अंग रही है, जो शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीला एवं बाल-केंद्रित बनाने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE, 1986) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि “सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक दोनों पहलुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा यह पूरी शिक्षण अवधि में विस्तारित होना चाहिए।” यह नीति इस बात पर बल देती है कि मूल्यांकन केवल परीक्षा तक सीमित न रहकर शिक्षण-अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए।

इसी दिशा में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF, 2005**)** ने एक ऐसे मूल्यांकन तंत्र की कल्पना की, जो पारंपरिक परीक्षा प्रणाली से भिन्न हो और जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों का प्रमुख मूल्यांकनकर्ता बनाया जाए। NCF 2005 के अनुसार विद्यालय-आधारित सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जिसके प्रमुख उद्देश्य हैं—

बच्चों पर परीक्षा का तनाव कम करना, मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाना, शिक्षकों को रचनात्मक शिक्षण के लिए अवसर प्रदान करना तथा मूल्यांकन को एक निदानात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करना, जिससे विद्यार्थियों में उच्च स्तर के कौशल विकसित किए जा सकें। सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि यह सरल, लचीली एवं सभी प्रकार के विद्यालयों में लागू करने योग्य हो—चाहे वे उच्च संसाधन वाले शहरी विद्यालय हों या ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में स्थित विद्यालय। इस संदर्भ में, परीक्षा सुधार NCF का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों पर पड़ने वाले मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करना है।

सतत एवं समग्र मूल्यांकन को "बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act)" में भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में सम्मिलित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों में सतत एवं समग्र मूल्यांकन को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया है। RTE Act (2009) का उद्देश्य बच्चों के ज्ञान, क्षमता एवं प्रतिभा का समुचित विकास करना है। यह अधिनियम इस बात पर बल देता है कि शिक्षा प्रक्रिया बाल-केंद्रित एवं गतिविधि-आधारित होनी चाहिए, जिसमें बच्चे अन्वेषण खोज एवं अनुभवों के माध्यम से सीखें। इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि बच्चे भय, तनाव एवं चिंता से मुक्त वातावरण में शिक्षा ग्रहण करें तथा अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकें। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान की समझ तथा उसके अनुप्रयोग की क्षमता का निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का राजनीतिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य यह दर्शाता है कि यह केवल एक मूल्यांकन प्रणाली नहीं है, बल्कि यह शिक्षा को अधिक लोकतांत्रिक, समावेशी एवं गुणवत्ता-उन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधार है, जो नीतिगत स्तर पर शिक्षा में समानता, गुणवत्ता एवं पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन

विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक आयु स्तर पर बालकों का संज्ञानात्मक, नैतिक एवं मनो-सामाजिक विकास भिन्न होता है। इसलिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन की गतिविधियाँ एवं मूल्यांकन पद्धतियाँ भी उसी के अनुरूप निर्धारित की जाती हैं।

तालिका: विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का संबंध

शिक्षा का स्तर	पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत	कोलबर्ग का नैतिक विकास	एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास	CCE गतिविधियाँ एवं मूल्यांकन पद्धति
प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा	पूर्व-संक्रियात्मक अवस्था मानसिक छवियाँ बनाना	पूर्व-पारंपरिक स्तर – सही/गलत का निर्णय परिणाम पर आधारित	पहल बनाम अपराधबोध	आनंदमय गतिविधियाँ, अनौपचारिक मूल्यांकन, अवलोकन, चेकलिस्ट
प्राथमिक शिक्षा	ठोस संक्रियात्मक अवस्था	नैतिकता का प्रारंभिक विकास	उद्योग बनाम हीनता	कक्षा गतिविधियाँ, लिखित परीक्षा, निदानात्मक परीक्षण, अवलोकन,

	तर्कसंगत सोच, वर्गीकरण क्षमता			मौखिक संवाद, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट
उच्च प्राथमिक शिक्षा	औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त चिंतन	पारंपरिक नैतिकता – सामाजिक नियमों पर आधारित निर्णय	पहचान बनाम भूमिका भ्रम (	असाइनमेंट, परियोजना कार्य, निदानात्मक परीक्षण, स्व एवं सहपाठी मूल्यांकन, ग्रेडिंग प्रणाली
माध्यमिक शिक्षा	उन्नत तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता	सामाजिक नियमों एवं मूल्यों की समझ	आत्म-पहचान का विकास	असाइनमेंट, परियोजना कार्य, सेमेस्टर प्रणाली, संचयी अभिलेख, स्व एवं सहपाठी मूल्यांकन
उच्च माध्यमिक शिक्षा	अमूर्त एवं विश्लेषणात्मक चिंतन का परिपक्व विकास	उच्च नैतिक निर्णय क्षमता	आत्म-स्थिरता एवं लक्ष्य निर्धारण	ट्यूटोरियल, मानदंड आधारित परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, क्रेडिट प्रणाली, ग्रेडिंग प्रणाली

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा

इस अवस्था में, Jean Piaget के अनुसार, भाषा विकास एवं कल्पनाशक्ति के विस्तार के कारण बच्चे प्रतीकात्मक एवं काल्पनिक खेलों में संलग्न होते हैं। यह अवस्था पूर्व-संक्रियात्मक कहलाती है।

पूर्व-प्राथमिक स्तर पर बालक मुख्यतः आनंदमय गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। इसलिए इस स्तर पर किसी भी प्रकार का औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन को अनौपचारिक एवं सहज रूप में किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव न पड़े।

यह भी आवश्यक है कि यदि किसी प्रकार के सुधारात्मक उपाय किए जाएँ, तो उन्हें भी सीखने की प्रक्रिया का ही हिस्सा बनाकर प्रस्तुत किया जाए, जिससे बच्चों को यह अनुभव न हो कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। इस प्रकार, इस स्तर पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों में सीखने के प्रति रुचि, आत्मविश्वास एवं स्वाभाविक विकास को प्रोत्साहित करना है।

प्राथमिक शिक्षा स्तर

✦ कक्षा I एवं II

कक्षा I एवं II के विद्यार्थी एक निर्माणात्मक (Formative) अवस्था में होते हैं, जहाँ उनके अधिगम की गति एवं व्यक्तित्व विकास अत्यंत तीव्र होता है। अतः इस स्तर पर मूल्यांकन की प्रकृति रचनात्मक होनी चाहिए, जिसमें सततता (Continuity) एवं समग्रता दोनों पर पर्याप्त बल दिया जाए।

इस स्तर पर मूल्यांकन मुख्यतः अवलोकन एवं मौखिक तकनीकों के माध्यम से किया जाना चाहिए, जो कक्षा गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता पर आधारित हो। यह संपूर्ण प्रक्रिया विद्यार्थियों के लिए बिना किसी औपचारिक निर्देश के स्वाभाविक रूप से संचालित होनी चाहिए, जिससे वे बिना दबाव के सीख सकें।

कक्षा III से V

कक्षा III से V के स्तर पर मूल्यांकन की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे यह समझने लगते हैं कि उनका परीक्षण किया जा रहा है। इसलिए इस स्तर पर मूल्यांकन अधिक औपचारिक हो जाता है।

इस स्तर पर भी अवलोकन एवं मौखिक तकनीकों का उपयोग जारी रहता है, किन्तु इसके साथ-साथ लिखित परीक्षाएँ भी मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण भाग बन जाती हैं। विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों की पहचान के लिए निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है, जिससे उपयुक्त सुधारात्मक उपायों का आयोजन किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, मानदंड-संदर्भित परीक्षण का उपयोग समय-समय पर विद्यार्थियों की दक्षताओं को निर्धारित स्तर तक मापने के लिए किया जाता है। सह-शैक्षणिक गुणों का मूल्यांकन निरंतर रूप से अवलोकन एवं रेटिंग स्केल के माध्यम से किया जाता है और इसकी रिपोर्ट प्रत्येक तीन माह में प्रस्तुत की जाती है।

विद्यार्थियों की प्रगति का संपूर्ण रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है, जिसमें उनके शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों की उपलब्धियों को संचित किया जाता है।

मूल्यांकन परिणामों को दर्शाने के लिए तीन-बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए पूर्ण ग्रेडिंग तथा सह-शैक्षणिक गुणों के लिए प्रत्यक्ष ग्रेडिंग अपनाई जाती है।

उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर

एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है, उसमें दक्षता प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस स्तर पर विद्यार्थियों की बढ़ती परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। मौखिक एवं लिखित परीक्षणों के अतिरिक्त असाइनमेंट एवं परियोजना कार्य को भी मूल्यांकन का महत्वपूर्ण अंग बनाया जाता है।

सतत एवं समग्र मूल्यांकन इस स्तर पर भी जारी रहता है, जिसमें विशेष रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए निदानात्मक एवं सुधारात्मक शिक्षण तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए समृद्धिकरण पर बल दिया जाता है। विभिन्न विषयों में दक्षताओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर मानदंड-संदर्भित परीक्षण का उपयोग किया जाता है।

सह-शैक्षणिक गुणों का मूल्यांकन निरंतर रूप से अवलोकन, रेटिंग स्केल एवं चेकलिस्ट के माध्यम से किया जाता है तथा इसकी रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही प्रस्तुत की जाती है। इस स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा स्व-मूल्यांकन एवं सहपाठी मूल्यांकन को भी मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा स्तर

इस स्तर पर मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि किसी भी विद्यार्थी को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाता है। पाठ्यक्रम को चार सेमेस्टरों में विभाजित किया जाता है, जिससे अधिगम को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सके।

मूल्यांकन मुख्यतः विद्यालय-आधारित होता है और सतत एवं समग्र मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत संचालित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से निदान एवं सुधार पर ध्यान दिया जाता है ताकि विद्यार्थियों में दक्षता स्तर सुनिश्चित किया जा सके। विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का आकलन समय-समय पर मानदंड-संदर्भित परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है।

विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नौ-बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से दर्शाया जाता है। सह-शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन अवलोकन, चेकलिस्ट एवं रेटिंग स्केल के माध्यम से किया जाता है तथा इसे पाँच-बिंदु प्रत्यक्ष ग्रेडिंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

प्रत्येक विद्यार्थी के लिए संचयी अभिलेख बनाए जाते हैं, जिनमें उनके विभिन्न परीक्षणों एवं गतिविधियों में प्रदर्शन का विवरण होता है। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में उनका स्व-मूल्यांकन एवं सहपाठी मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हालाँकि, व्यवहार में इस प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन कई स्थानों पर नहीं हो पाया। उदाहरणस्वरूप, असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 1998 में इसे लागू किया गया, किन्तु इसका वास्तविक क्रियान्वयन सीमित रहा। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भी इस अवधारणा को केवल सैद्धांतिक रूप से पढ़ाया गया, जिससे शिक्षक इसके व्यावहारिक उपयोग से अपरिचित रहे। उचित प्रशिक्षण के अभाव में शिक्षक इस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सके।

उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर

इस स्तर पर मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ किया जाता है, ताकि विद्यार्थियों को न केवल उच्च शिक्षा (Tertiary Education) के लिए बल्कि जीवन के लिए भी तैयार किया जा सके। पाठ्यक्रम को चार सेमेस्टरों में विभाजित किया जाता है तथा यह क्रेडिट प्रणाली पर आधारित होता है। पहले तीन सेमेस्टर की परीक्षाएँ विद्यालय द्वारा आयोजित की जाती हैं, जबकि चौथे सेमेस्टर की परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है। यह प्रणाली विद्यार्थियों को लचीलापन प्रदान करती है, जिससे वे अपनी गति के अनुसार क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। इस स्तर पर ट्यूटोरियल्स को भी मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। विद्यालय स्तर पर मानदंड-संदर्भित परीक्षणों के माध्यम से दक्षता-

आधारित अधिगम पर बल दिया जाता है, जबकि बोर्ड स्तर पर मानक-संदर्भित परीक्षण का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नौ-बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसमें अंक को सीधे ग्रेड में परिवर्तित किया जाता है। सह-शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन पाँच-बिंदु प्रत्यक्ष ग्रेडिंग द्वारा किया जाता है, जिसे प्रत्येक सेमेस्टर में दर्ज किया जाता है। इस प्रणाली में विद्यार्थियों को अपने ग्रेड में सुधार करने के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे निरंतर प्रगति कर सकें।

सतत एवं समग्र मूल्यांकन की चुनौतियाँ

सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि सभी शिक्षक उचित प्रशिक्षण प्राप्त करें और एक समान मूल्यांकन पद्धति का पालन करें। किन्तु व्यवहार में इस प्रणाली में कई प्रकार की असंगतियाँ देखने को मिलती हैं।

सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षकों को न केवल विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन करना होता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य आदतों, कार्य व्यवहार, स्वच्छता एवं सहयोग जैसे पहलुओं का भी आकलन करना होता है। ये सभी पहलू काफी हद तक व्यक्तिपरक होते हैं, जिससे मूल्यांकन में भिन्नता एवं पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। हालाँकि शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से इन समस्याओं को कम करने का प्रयास किया जाता है, फिर भी यह मानकीकृत परीक्षाओं की तुलना में अधिक सुसंगत परिणाम प्रदान नहीं कर पाता।

सतत एवं समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के साथ-साथ उनके दृष्टिकोण, विश्वास एवं मूल्यों का निर्माण करना है, किन्तु इसमें पूर्वाग्रह का खतरा भी बना रहता है, विशेषकर अल्पसंख्यक या विभिन्न सामाजिक समूहों के संदर्भ में। इसके विपरीत, मानकीकृत परीक्षाएँ ऐसे विद्यार्थियों को भी अपनी क्षमता सिद्ध करने का अवसर प्रदान करती हैं, जिनके मूल्यांकन पर शिक्षक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ सकता है।

भिन्न स्तरों पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन की चुनौतियाँ

विद्यार्थी स्तर

विद्यार्थी स्तर पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत सह-शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता होती है। साथ ही, विद्यार्थियों को शैक्षणिक (Scholastic) एवं सह-शैक्षणिक (Co-scholastic) दोनों पक्षों पर समान रूप से ध्यान देना होता है, जो कई बार उनके लिए संतुलन बनाना कठिन बना देता है।

शिक्षक स्तर

शिक्षक स्तर पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन के क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ सामने आती हैं। शिक्षकों में कई बार आवश्यक ज्ञान एवं कौशल का अभाव होता है, जिससे वे इस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त, समय की कमी एवं आवश्यक संसाधनों की अनुपलब्धता भी एक बड़ी समस्या है।

प्रधानाचार्य एवं सहकर्मियों द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण करने का दबाव भी शिक्षकों पर बना रहता है। सामाजिक अपेक्षाएँ एवं बाहरी उत्तरदायित्व भी शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण की कमी, कार्यभार की अधिकता, तथा कभी-कभी पक्षपात एवं अनुचित व्यवहार भी सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं।

प्रधानाचार्य स्तर

प्रधानाचार्य स्तर पर भी कई प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय समस्याएँ देखने को मिलती हैं। राज्य स्तर से उचित मार्गदर्शन का अभाव, वित्तीय संसाधनों की कमी तथा विद्यालय में आवश्यक भौतिक संरचना का अभाव प्रमुख समस्याएँ हैं।

इसके अतिरिक्त, पूरे मूल्यांकन तंत्र की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य पर होती है, जिससे उन पर कार्यभार बढ़ जाता है। विभिन्न गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं के समन्वय में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

अभिभावक एवं समुदाय स्तर

सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत अभिभावकों को बच्चों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो कई बार उनके लिए समय एवं आर्थिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है।

विद्यालय एवं बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी अभिभावकों एवं समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। साथ ही, यह प्रक्रिया समय-साध्य होने के कारण सभी के लिए इसे निरंतर बनाए रखना कठिन हो सकता है।

सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्रियान्वयन

सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करने में अधिक समय देना पड़ता है। यद्यपि इससे विद्यार्थियों की प्रगति का व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होता है तथा अभिभावकों के साथ संवाद बढ़ता है, फिर भी यह शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार डालता है, जो उनके मूल्यांकन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इस प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों के साथ बैठकें अधिक बार आयोजित की जाती हैं, जिससे शिक्षकों को अपने कार्य समय में अतिरिक्त समय देना पड़ता है। इस समस्या का समाधान तब संभव है, जब अभिभावक विद्यालय समय में उपलब्ध हों तथा कक्षा का आकार सीमित रखा जाए।

सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है—

- पाठ्यक्रम का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर अधिगम उद्देश्यों एवं दक्षताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए।
- मूल्यांकन उपकरणों का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि वे मानदंड-संदर्भित हों और दक्षताओं का सही आकलन कर सकें।
- शिक्षण एवं मूल्यांकन के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा मूल्यांकन विकृत हो सकता है।
- विद्यार्थियों की दक्षताओं के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण का भी समग्र मूल्यांकन किया जाए।
- विद्यार्थियों की प्रगति का नियमित एवं व्यवस्थित अभिलेख बनाए रखा जाए।
- शिक्षकों में मूल्यांकन संबंधी ज्ञान, कौशल, प्रतिबद्धता एवं सुधारात्मक शिक्षण प्रदान करने की क्षमता का विकास किया जाए।
- शैक्षणिक एवं तकनीकी अवसंरचना में सुधार किया जाए।
- कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाए।
- समुदाय, विद्यार्थियों एवं अधिकारियों के बीच किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचा जाए।
- नैतिक जिम्मेदारी का पालन किया जाए।
- पाठ्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए

निष्कर्ष

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पारंपरिक रूप से मूल्यांकन मुख्यतः विद्यार्थियों के ज्ञान एवं समझ को मापने तक सीमित रहा है। कौशलों एवं उच्च स्तरीय मानसिक क्षमताओं का मूल्यांकन अपेक्षाकृत कम किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों के गैर-संज्ञानात्मक पक्षों जैसे—रुचियाँ, दृष्टिकोण, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का मूल्यांकन प्रायः उपेक्षित रहा है। शैक्षिक नीतियों एवं पाठ्यचर्या रूपरेखाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि मूल्यांकन को समग्र बनाया जाना चाहिए, जिसमें शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक सभी पहलुओं का आकलन किया जाए। समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत न केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन किया जाता है, बल्कि स्वास्थ्य आदतों, कार्य व्यवहार, स्वच्छता, सहयोग एवं अन्य सामाजिक गुणों का भी सरल एवं व्यावहारिक उपकरणों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रणाली न केवल विद्यार्थियों के प्रदर्शन के विभिन्न स्तरों का आकलन करने में सहायक होती है, बल्कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से संबंधित निर्णय लेने, विद्यार्थियों के उन्नयन, शिक्षा की गुणवत्ता, दक्षता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन तकनीकों एवं उपकरणों का उपयोग आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थियों के विकास के विभिन्न आयामों के लिए अलग-अलग मूल्यांकन विधियों की आवश्यकता होती है। अतः स्पष्ट है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन तकनीकों एवं उपकरणों का उपयोग आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थियों के विकास के विभिन्न आयामों के लिए अलग-अलग मूल्यांकन विधियों की आवश्यकता होती है। इसलिए शिक्षक को प्रत्येक

परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त तकनीक का चयन करना चाहिए, आवश्यक उपकरण विकसित करने चाहिए तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, विश्वसनीय एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाना चाहिए।

References

1. Du Plessis, J. (2003). Rainbow charts and C-O-C-O-N-U-T-S: Teacher development for continuous assessment in Malawi classrooms. American Institutes for Research.
2. Jadal, M. M. (2011). Effect of continuous and comprehensive evaluation on students' attainment at primary level. International Referred Research Journal, 3(32), September.
3. Mohanty, S. B. (2009). A review of national curriculum framework for teacher education: Towards preparing professional and humane teacher. National Council for Teacher Education.
4. National Council for Teacher Education. (2009a). National curriculum framework for teacher education 2009 (Draft for discussion). Author.
5. National Council for Teacher Education. (2009b). National curriculum framework for teacher education: Towards preparing professional and humane teacher. Author.
6. National Council for Teacher Education & National Council of Educational Research and Training. (2006). Curriculum framework for teacher education (Draft). NCTE.
7. Rao, M. P., & Rao, P. (n.d.). Effectiveness of continuous and comprehensive evaluation over the evaluation practices of teachers.
8. Rao, M. P. (2001). Effectiveness of the continuous and comprehensive evaluation training programme over the evaluation practices of primary school teachers: A DPEP research study in Tamil Nadu. Regional Institute of Education, Mysore.
9. Rao, M. P., & Kulkarni, S. P. (2002). Development and implementation of a school-based evaluation system at primary stage in demonstration school. Regional Institute of Education, Mysore.
10. Ministry of Human Resource Development. (1992). National policy on education, 1986 (As modified in 1992). Department of Education, Government of India.
11. National Council of Educational Research and Training. (2005). National curriculum framework 2005. NCERT.
12. Ministry of Law and Justice. (2009). The right of children to free and compulsory education act, 2009. Government of India.